कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस को जून तिमाही में 275 करोड़ रुपये के घाटे की आशंका

नई दिल्ली, एजेंसी। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान उच्च मृत्यु दर के कारण उसकी जीवन बीमा शाखा को जून 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान 275 करोड़ रुपये तक घाटे की आशंका है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस ने शेयर बाजार को बताया, ''दूसरी लहर के कारण बढ़े हुए दावों और उच्च मृत्यु दर से संबंधित प्रावधानों के कारण कंपनी को जून तिमाही के दौरान 225-275 करोड़ रुपये के नुकसान की आशंका है।'' कंपनी ने कहा कि आगे के प्रावधान मृत्यु दर के रुझान पर निर्भर करेंगी। निजी बीमाकर्ता ने कहा, ''कंपनी के पास मजबूत पूंजी और अदायगी क्षमता की स्थिति बनी हुई है।''

आइकिया ने बेंगलुरु में ई-कॉमर्स, मोबाइल शॉपिंग ऐप की शुरुआत की

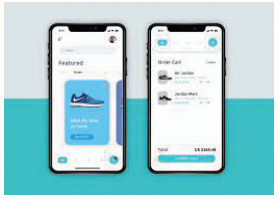

बेंगलुरु, 17 जून (ए)। फर्नीचर के खुदरा कारोबार से जुड़ी कंपनी आइकिया ने गुरुवार को बेंगलुरु में अपनी ई-कामर्स सेवाओं और मोबाइल शॉपिंग ऐप को पेश करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस ऐप के जरिए 8,000 से अधिक घरेलू साज-सज्जा के उत्पाद और समाधान होंगे। कंपनी ने दिसंबर 2020 में नवी मुंबई में अपना दूसरा आइकिया इंडिया स्टोर खोला था। आइकिया की हैदराबाद, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में पहले ही ऑनलाइन उपस्थिति है। बयान में कहा गया कि आइकिया मोबाइल शॉपिंग ऐप में आसान खोज और ब्राउजिंग अनुभव के साथ उत्पाद सिफारिश, रेटिंग और समीक्षा के विकल्प शामिल हैं। आइकिया इंडिया के सीईओ पीटर बेटजेल ने कहा कि कंपनी के लिए कर्नाटक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाजार है और आने वाले समय में बेंगलुरु के भीतर एक सिटी सेंटर स्टोर भी खोला जाएगा।

अमेजन-फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की

नई दिल्ली, 17 जून (ए)। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच कर रहा है। इस जांच को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अमेजन और फ्लिपकार्ट ने सीसीआइ की जांच को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ डिविजन बेंच में नई अपील दाखिल की है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह सीसीआइ की जांच को हरी झंडी दे दी थी। दोनों कंपनियों पर प्रतिस्पर्धी व्यवहार विरोधी का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने बुधवार को देर शाम अपील दाखिल की है। वहीं, अमेजन इंडिया ने गुरुवार सुबह अपील दाखिल की है। इन दोनों अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। दोनों कंपनियों ने अलग-अलग अपील दाखिल की है। कोर्ट दोनों अपीलों को एक साथ जोड़कर सुनवाई कर सकता है। हालांकि, दोनों अपीलों को जोड़ने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस मामले से वाकिफ एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। सीसीआइ ने पिछले साल जनवरी में अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच का आदेश दिया था। सीसीआइ ने कहा था कि कंपटीशन एक्ट 2002 के सेक्शन 26(1) के तहत जांच करने के लिए प्रथमदृष्टया सभी सबूत मौजूद हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और दिल्ली व्यापार महासंघ ने अमेजन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर ग्राहकों को ज्यादा डिस्काउंट देने और कुछ सेलर्स को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद ही सीसीआइ ने जांच का आदेश दिया था।

अगर नहीं है आपके पास फॉर्म-16 तो भी फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

नई दिल्ली, 17 जून (ए)। नौकरीपेशा लोगों को प्रत्येक वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। जिसके लिए उन्हें फॉर्म-16 की जरुरत पड़ती है। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं मिल सका या उसमें देरी हो रही है तो उसके बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अब आपको कुछ डॉक्युमेंट्स एकत्र करने होंगे। जिसमें सैलरी स्लिप, फॉर्म 26 एएस या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट जो ट्रेसेस की वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएगा। वहीं रिटर्न फाइल करते वक्त आपको रेंट एग्रीमेंट और आपने कहांङ्कहां निवेश किया है उसके डॉक्युमेंट की जरुरत होगी। जिसके बाद आप आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे फॉर्म 16 काफी जरूरी डॉक्युमेंट होता है। जिसमें आपके सभी तरह के टैक्स का रिकॉर्ड होता है। जो आपकी कंपनी आपकी सैलरी से डिडक्ट करती है। इसे सैलरी सर्टिफिकेट भी कहा जाता है। जिस तरह से प्रत्येक माह मिलने वाली सैलरी स्लिप जरुरी है उसी तरह से फॉर्म 16 भी काफी जरूरी है। आइए आपको भी बताते हैं कि फॉर्म 16 के बिना आप रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ईयर की सभी सैलरी स्लिप को एकत्र करना होगा।

अगर आपने कंपनी भी चेंज भी है तो दोनों की सैलरी स्लिप की डिटेल देनी होगी।

राज्यों में प्रतिबंध हटने से जून में बढ़ी आर्थिक गतिविधियां, ज्यादा वैक्सीनेशन से ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी

अर्थव्यवस्था के लिए सुनहरे संकेत

नई दिल्ली,17 जून (ए)। कोविड संक्रमण की मार झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर आई है। कोरोना के केसों में कमी और राज्यों में प्रतिबंध हटने से जून में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। तीन प्रमुख रिसर्च एजेंसियों के साप्ताहिक डाटा के अनुसार, 13 जून को समाप्त हुए सप्ताह में आर्थिक गतिविधियों में लगातार तीसरे सप्ताह सुधार रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के सेंटिमेंट में भी सुधार हो रहा है।

क्या कहते हैं प्रमुख इंडिकेटर?: यूबीएस इंडिया एक्टिविटी इंडिकेटर 13 जून को समाप्त हुए सप्ताह में उच्च स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना के केसों में बढ़ोतरी के साथ 23 मई को समाप्त हुए सप्ताह में यह निचले स्तर पर पहुंच गया था। इसी तरह से क्वांटइको सिंचर्ज का डेली एक्टिविटी एंड रिकवरी ट्रैकर संकेत देता है कि 23 जून को समाप्त हुए सप्ताह में आर्थिक गतिविधियों में लगातार चौथे सप्ताह सुधार हुआ है।

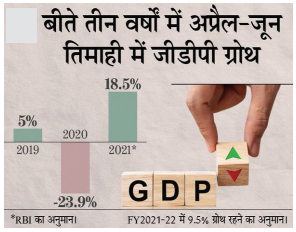

मोबिलिटी इंडिकेटर्स और बिजली की ज्यादा डिमांड के कारण नोमुरा का बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स लगातार तीसरे सप्ताह आर्थिक गतिविधियों में सुधार का संकेत देता है। 23 मई को समाप्त हुए सप्ताह में नोमुरा का बिजनेस इंडेक्स 1 साल के निम्न स्तर पर पहुंच गया था।

ई-वे बिल और इंपोर्ट में भी रहा सुधार : मोबिलिटी इंडिकेटर जैसे गूगल मोबिलिटी इंडिसीज, ऐपल ड्राइविंग इंडेक्स और रेल यात्रियों का दैनिक रेवेन्यू भी जून में मजबूत रिकवरी का संकेत देते हैं। जून के पहले 15 दिनों में ई-वे बिल और इंपोर्ट में बढ़ोतरी भी आर्थिक गतिविधियों में लगातार सुधार का संकेत दे रहे हैं।

कमजोर उपभोक्ता सेंटिमेंट के कारण धीरे-धीरे होगी रिकवरी: जैन : यूबीएस की इकोनॉमिस्ट तन्वी गुप्ता जैन का कहना है कि हम जून से आर्थिक गतिविधियों में क्रमिक रूप से तेजी की उम्मीद कर रहे हैं। 2020 की वी-शेप रिकवरी के विपरीत, हम भारत की धीरे-धीरे रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं।

वैक्सीनेशन में तेजी रिकवरी की राह पर आएगी अर्थव्यवस्था

कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन में तेजी से अर्थव्यवस्था रिकवरी की राह पर आ पाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा बुलेटिन में एक आर्टिकल में यह बात कही गई है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी नाम से इस आर्टिकल को डिप्टी गवर्नर एमडी पात्रा और आरबीआइ के अन्य अधिकारियों ने लिखा है। इस आर्टिकल में लिखा है, मौजूदा असेसमेंट यह है कि कोविड की दूसरी लहर का घरेलू मांग पर प्रमुख असर पड़ा है।

हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा

आर्टिकल में कहा गया है कि वैक्सीन से अपने आप महामारी समाप्त नहीं होगी। हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। वैक्सीन के साथ हेल्थकेयर, लॉजिस्टिक्स और रिसर्च में निवेश बढ़ाना होगा। कोरोना महामारी वास्तविक परिणामों के साथ एक वास्तविक झटका है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बिजनेस इनवेस्टमेंट और उत्पादकतों ग्रोथ की ठोस नींव बनी रहे। आर्टिकल में कहा गया है कि यह लेखकों के अपने विचार हैं। आरबीआइ का इनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।

अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और गाड़ी का परमिट

नई दिल्ली, 17 जून (ए)। केंद्र सरकार ने एक बार फिर वाहनों से जुड़े कागजातों की वैधता अवधि को बढ़ा दिया है। देश में जारी कोरोना के कहर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और वाहनों के परमिट और फिटनेस 30 सितंबर 2021 तक मान्य रहेंगे।

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि एनफोर्समेंट अधिकारी फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन और अन्य सभी संबंधित कागजातों की वैधता 30 सितंबर 2021 तक मानें। इसमें वे सभी कागजात शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 के बाद या 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने जा रही है। मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से नागरिकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाएं लेने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने की सलाह दी है।

माइक्रोसॉफ्ट ने सत्य नडेला को बनाया कंपनी का चेयरमैन

नई दिल्ली, 17 जून (ए)। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने भारतवंशी सीईओ सत्य नडेला को कंपनी का अध्यक्ष बनाया है, जिस अतिरिक्त भूमिका में वह ''बोर्ड का एजेंडा निर्धारित करने में अगुवाई करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने बुधवार को घोषणा की कि बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों ने सर्वसम्मति से नडेला को बोर्ड के अध्यक्ष की भूमिका के लिए चुना। इसके अलावा जॉन डब्ल्यू थॉम्पसन को सर्वसम्मति से मुख्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया। वह इस भूमिका को 2012 से 2014 तक पहले भी निभा चुके हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, ''इस भूमिका में, नडेला बोर्ड के लिए एजेंडा तय करने के काम का नेतृत्व करेंगे, सही रणनीतिक अवसरों का लाभ लेने और मुख्य जोखिमों की पहचान करने तथा उनके असर को कम करने के लिए कारोबार की अपनी गहरी समझ का लाभ उठाएंगे। नडेला (53), थॉम्पसन की जगह लेंगे, जो मुख्य स्वतंत्र निदेशक के रूप में आगे अपनी भूमिका निभाएंगे।

22 हजार करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू: पेटीएम ने आइपीओ की जिम्मेदारी जेपी मॉर्गन को सौंपा

मुंबई ,17 जून (ए)। देश की लीडिंग डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम 2021 में अपना आइपीओ लॉन्च करने जा रही है। इसके जरिए करीब 22 हजार करोड़ रुपए जुटाएगी। ताजा अपडेट यह है कि कंपनी ने पब्लिक इश्यू के लिए जेपी मार्गन, गोल्डमैन सैक्स, आइसीआइसीआइ सिक्योरिटीज और मॉर्गन स्टैनली को इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर हायर किया है।

देश का सबसे बड़ा आइपीओ हो सकता है : पेटीएम पर मालिकाना हक वन97 कम्युनिकेशंस का है। वन97कम्युनिकेशन का वैल्यूएशन करीबन 2 से 2.20 लाख करोड़ रुपए है। खास बात यह है कि अगर पेटीएम की आइपीओ लॉन्चिंग सफल होती है, तो यह भारतीय बाजार का सबसे पब्लिक इश्यू होगा। फिलहाल यह तगमा सरकारी कंपनी कोल इंडिया के नाम है। कोल इंडिया ने 2010 में 15,200 करोड़ रुपए जुटाए थे। ब्लूमबर्ग के मुताबिक कंपनी जुलाई में मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स फाइल कर सकती है। घरेलू फिनटेक कंपनी में अलीबाबा के एंट ग्रुप की 29.71 प्रतिशत, सॉफ्ट बैंक विजन फंड की 19.63 प्रतिशत और सैफ पार्टनर्स की 18.56 प्रतिशत बड़ी हिस्सेदारी है। कंपनी के ओनर विजय शेखर शर्मा की हिस्सेदारी 14.67 प्रतिशत है। इसके अलावा एजीएच्च होल्डिंग्स, टी रोवे प्राइस और डिस्कवर कैपिटल, बार्कशेयर हैथवे की हिस्सेदारी है।

मर्चेंट पेमेंट मार्केट में कंपनी की बड़ी हिस्सेदारी

बाजार में पेटीएम का मुकाबला वालमार्ट की फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे और फेसबुक के वॉट्सऐप पे के साथ है। यह घरेलू मर्चेंट पेमेंट के मामले में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखती हैं। पेटीएम के पास 2 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट पार्टनर्स हैं। इसके ग्राहक महीने में लगभग 1.4 अरब ट्रांजेक्शन करते हैं।

पेटीएम का फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पर है

वन97 कम्युनिकेशन बोर्ड ने पिछले ही दिनों एक मीटिंग में आइपीओ को मंजूरी दे दी थी। दरअसल, पेटीएम के फाउंडर में विजय शेखर शर्मा पिछले कुछ सालों से रेवेन्यू को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। यह कंपनी डिजिटल से आगे बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल सर्विसेस, वेल्थ मैनेजमेंट और डिजिटल वॉलेट की सेवाएं देती है। यह यूपीआइ बेस्ड पेमेंट सर्विस देती है।

ऑनलाइन आईटी कौशल सेगमेंट में एक नए स्टार्टअप आई-टेक का प्रवेश

नई दिल्ली, 17 जून (ए)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में छात्रों में 21वीं सदी के कौशल विकसित करने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, सिखाए गए कौशल और प्रदान किए गए कौशल के बीच बहुत बड़ा अंतर मौजूद है। यदि छात्रों को कम उम्र से ही प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो इस अंतर को पूर्ण किया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ आई-टेक की स्थापना की है, जो कक्षा 6 से 12 (विज्ञान, वाणिज्य और कला शाखा) के छात्रों के लिए 100 प्रतिशत ऑनलाइन आईटी कौशल प्रशिक्षण मंच है। आई-टेक कोर्स(पाठ्यक्रम) प्रौद्योगिकी कौशल - कोडिंग, आइटी फंडामेंटल्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पायथन, आदि और संज्ञानात्मक शिक्षण - आत्म संवर्धन, माइंड मैपिंग, सामान्य ज्ञान आदि को जोड़ देगा।

डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन डबल से भी ज्यादा

नई दिल्ली, 17 जून (ए)। चालू वित्त वर्ष में अबतक डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन दोगुना से अधिक होकर 1.85 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। इसका मुख्य कारण व्यक्तिगत आयकर और अग्रिम कर भुगतान में वृद्धि है। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में शामिल कंपनी आयकर (सीआईटी) संग्रह 74,356 करोड़ रुपये जबकि प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) समेत व्यक्तिगत आयकर संग्रह 1.11 लाख करोड़ रुपये रहा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि वापस की गयी टैक्स राशि को हटाकर शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह एक अप्रैल से 15 जून के बीच 1,85,871 करोड़ रुपये रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 92,762 करोड़ रुपये था। यानी पिछले साल के मुकाबले इसमें 100.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में अबतक 30,731 करोड़ रुपये कर वापस किये गये हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में अबतक सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह 2.16 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 1.37 लाख करोड़ रुपये था। बयान के अनुसार सकल कंपनी आयकर संग्रह 96,923 करोड़ रुपये जबकि व्यक्तिगत आयकर 1.19 लाख करोड़ रुपये रहा।

एंड्रायड पर टू कॉलर नई महत्वपूर्ण क्षमताओं के साथ अपडेट हुआ

बेंगलुरू, 17 जून (ए)। कॉलर आईडी एवं स्पैम डिटेक्शन का दूसरा नाम, टू कॉलर यूजर के अनुभव में सुधार के लिए नई विशेषताएं प्रस्तुत कर रहा है। इन नई विशेषताओं में ग्रुप वॉइस कॉलिंग, स्मार्ट एसएमएस एवं इनबॉक्स क्लीनर हैं। यह सभी विशेषताएं यूजर के फीडबैक पर आधारित हैं और हमारे उपभोक्ताओं की विकसित होती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ग्रुप वॉइस कॉल्स के साथ उपभोक्ता एक साथ अधिकतम आठ लोगों को क्रॉस-बॉर्डर वॉइस कॉल्स कर सकेंगे। स्मार्ट एसएमएस नई विशेषताएं प्रस्तुत करता है, जो दैनिक संचार को बहुत ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अंत में, इनबॉक्स क्लीनर द्वारा उपभोक्ता गैरजरूरी संदेशों को हटाकर अपने फोन का स्पेस फ्री कर सकते हैंइन नई विशेषताओं के बारे में रिंषित झुनझुनवाला, एमडी इंडिया, टू कॉलर ने कहा, ''हम अपने ग्राहकों की विकसित होती हुई जरूरतों और अभिनव समाधानों द्वारा उन जरूरतों को पूरा करने पर केंद्रित हैं।

खाने के तेल सस्ते हुए:कीमतों में 10-20 प्रतिशत की आई गिरावट, पिछले महीने आसमान पर पहुंची थी कीमत

मुंबई, 17 जून (ए)। महिलाओं की रसोई के लिए राहत की बात है। पिछले कुछ दिनों में खाने की तेल की कीमतों में 10-20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने इस तरह की जानकारी दी है। इसके मुताबिक एक महीने में इन कीमतों में कमी आई है।

मंत्रालय के मुताबिक, तेलों की अलग-अलग कैटगरी में 20 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। इसमें पाम ऑयल की कीमत 19 प्रतिशत घट कर 115 रुपए प्रति लीटर आ गई है। यह पहले 142 रुपए किलो था। जबकि सनफ्लावर तेल की कीमत 16 प्रतिशत घट कर 157 रुपए लीटर पर आ गई है। इसकी पहले कीमत 188 रुपए थी। आंकड़ों के मुताबिक 15 लीटर तेल के डिब्बे की बात करें तो इसमें भी गिरावट दिखी है। सरसों के तेल का 15 लीटर का डिब्बा अब 2,325 रुपए में मिल रहा है जो पहले 2,655 रुपए में मिल रहा था। पामतेल के 15 लीटर के डिब्बे की कीमत 1,900 रुपए पर आ गई है। यह पहले 2,200 रुपए थी। सनफ्लावर के तेल की बात करें तो इसका 15 लीटर का डिब्बा 2,500 रुपए से घट कर 2,250 रुपए पर आ गया है। मूंगफली के तेल की कीमत 2,700 रुपए से घट कर 2,600 रुपए पर आ गई है। सबसे कम गिरावट इसी तेल की कीमत में आई है। सोयाबीन के तेल की कीमत 1,400 रुपए से कम हो कर 2,100 रुपए पर आ गई है। आंकड़ों के मुताबिक, मूंगफली तेल की कीमत एक लीटर की 190 से घट कर 174 रुपए पर आई है। वनस्पति तेल की कीमत एक लीटर की 154 से कम होकर 141 रुपए पर आई है। इन दोनों तेलों की कीमतों में 8-8 प्रतिशत की कमी आई है। सोया ऑयल की कीमत भी इसी तरह घटी है। इसकी पहले की कीमत 162 रुपए थी जो अब 138 रुपए पर है। यानी 15 प्रतिशत इसकी कीमतों में कमी आई है।

सरसों के एक लीटर तेल की कीमत भी 175 से घट कर 157 रुपए पर आ गई है।

भारत खाने के तेल का आयात करता है

भारत को खाद्य तेल की अपनी जरूरत के बड़े हिस्से का आयात करना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि खपत के मुकाबले देश में खाद्य तेलों का उत्पादन काफी कम होता है। हालांकि मांग में आई भारी गिरावट के बीच विदेशों में खाद्य तेलों के भाव टूटे हैं। देश में इस हफ्ते की शुरुआत में तेल तिलहन बाजार में सरसों, तिलहन, सोयाबीन एवं मूंगफली तेल तिलहन, बिनौला, सीपीओ और पामोलीन तेल कीमतों के भाव गिरावट के साथ बंद हुए थे।

8 जून से मिलावट पर रोक

आठ जून से किसी भी साधारण तेल का सरसों तेल के साथ मिलावट किए जाने पर कानूनी रोक लगा दी गई है। सरसों में मिलावट के लिए ज्यादातर सोयाबीन डीगम और चावल भूसी तेल का इस्तेमाल होता है। मिलावट पर रोक के बाद सोयाबीन डीगम और कच्चा पॉम तेल (सीपीओ) की मांग काफी कमजोर हो गई जिससे पूरे कारोबार में नरमी का रुख कायम हो गया।